मेक इन इंडिया से महिलाओं को मिला बड़ा रोजगार

आईफोन फैक्ट्रियों में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं काम पर

देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को बड़ा लाभ मिला

नई दिल्ली, 16 मार्च. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में आईफोन निर्माण इकाइयों में एक लाख से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं.

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश की कई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों में कुल कार्यबल का आधे से अधिक हिस्सा महिलाएं हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है.महिलाएं अब केवल असेंबली लाइन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे जटिल तकनीकी क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. भारत में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का असर उत्पादन और निर्यात दोनों पर दिखाई दे रहा है. खासकर स्मार्टफोन और आईफोन उत्पादन में तेजी आई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को बड़ा लाभ मिल रहा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और इसके साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में आईफोन निर्माण इकाइयों में एक लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं.

> कंपनी हर साल दुनियाभर में करीब 22 से 23 करोड़ आईफोन का उत्पादन करती है. निर्यात के क्षेत्र में भी स्मार्टफोन ने नया रिकॉर्ड बनाया है. 2025 में आईफोन भारत से निर्यात होने वाला सबसे मूल्यवान उत्पाद बन गया, जिसका निर्यात लगभग 23 अड़ुरब डॉलर रहा. इसके साथ ही पहली बार स्मार्टफोन भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बनकर उभरे हैं. जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान भारत से स्मार्टफोन का कुल निर्यात लगभग 30.13 अरब डॉलर रहा, जिसमें एप्पल की हिस्सेदारी करीब 76 प्रतिशत बताई गई है.

नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल ने महिलाओं को रोजगार देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मंत्री के अनुसार देश की कई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयों में कुल कार्यबल का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा महिलाएं हैं. यह केवल सामान्य उत्पादन कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं अब सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे तकनीकी और जटिल क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं.

इससे यह संकेत मिलता है कि भारत में तकनीकी उद्योग में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. भारत में एप्पल के इकोसिस्टम ने भी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

कंपनी से मिला 1,600 मेगावाट बिजली आपूर्ति पत्र

5.30 रुपए प्रति यूनिट की दर की बोली के आधार पर हासिल किया यह अनुबंध

अहमदाबाद, 16 मार्च. निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी अडाणी पावर लि. (एपीएल) ने रविवार को बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (एमएसईडीसीएल) से 1,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का अनुबंध-पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ है.

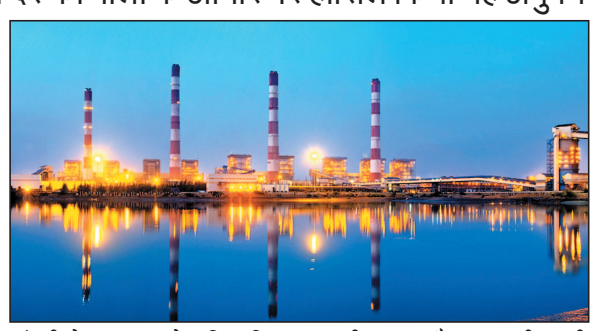

कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वह यह बिजली अपनी कुछ निर्माणाधीन अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं में एक से देगी. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे एमएसईडीसीएल यह अनुबंध एक काफी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में सफलता के बाद मिला है, जिसमें कंपनी ने सबसे कम दर पर बिजली देने की बोलीदाता थी. कंपनी ने 5.30 रुपये प्रति यूनिट की दर की बोली के आधार पर यह अनुबंध हासिल किया है. यह एक 25-वर्षीय बिजली आपूर्ति समझौता (पीएसए) होगा और आपूर्ति 2030-31 से शुरू की जाएगी. एपीएल के सीईओ एबी खियाली ने ने कहा, यह अनुबंध अडाणी पावर की लागत संरचना की प्रतिस्पर्धात्मकता, भरोसेमंद बेसलोड बिजली प्रदान करने की हमारी क्षमता और भारत की बढ़ती बिजली आवश्यकताओं को दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. कंपनी कि अडाणी पावर ने अब अपने 23800 मेगवाट की अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 13300 मेगावाट के लिए दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति समझौते (पीएसए) सुनिश्चित कर लिए हैं.

डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे की आईपीओ लिस्टिंग टली

ग्लोबल अनिश्चितता के बीच निवेशकों की सतर्कता

बाजार में उतार-चढ़ाव : फोनपे ने टाला आईपीओ प्लॉन

नई दिल्ली, 16 मार्च. भारत की प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने फिलहाल अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) की प्रक्रिया को टाल दिया है. कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और बाजार में जारी भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

कंपनी का कहना है कि जब तक ग्लोबल कैपिटल मार्केट में स्थिरता नहीं आती, तब तक वह अपनी पब्लिक लिस्टिंग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी. फोनपे के सीईओ समीर निगम ने कहा कि कंपनी भारत में ही लिस्टिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन मौजूदा जियो-पॉलिटिकल तनाव और निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए फिलहाल सही समय का इंतजार किया जा रहा है. डिजिटल पेमेंट सेक्टर में तेजी से बढ़ रही इस कंपनी ने 2016 में अपना एप लॉन्च किया था और आज इसके 65 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं. कंपनी का नेटवर्क देशभर में 4.7 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स तक फैला हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है, जिसका असर बड़ी कंपनियों के आईपीओ प्लान पर भी पड़ रहा है.

भारत की प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे ने फिलहाल अपनी पब्लिक मार्केट लिस्टिंग यानी आईपीओ की प्रक्रिया को टालने का फैसला किया है.

> आज फोनपे केवल पेमेंट एप नहीं है, बल्कि यह कई अन्य क्षेत्रों में भी सेवाएं दे रही है. कंपनी के प्रमुख वर्टिकल में कंज्यूमर पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स, लेंडिंग, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर मार्केट सर्विसेज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में इंडस ऐपस्टोर नाम से एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप मार्केटप्लेस भी लॉन्च किया है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन और निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर पड़ा है. ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में निवेश करने से पहले ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं.

थोक मुद्रास्फीति फरवरी में बढ़कर 11 महीने के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली, 16 मार्च. तिलहन और खनिजों की कीमतों में भारी उछाल के साथ तंबाकू उत्पादों और बुनियादी धातुओं की कीमतों में वृद्धि से इस साल फरवरी में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.13 प्रतिशत पर पहुंच गयी. थोक महंगाई की यह दर पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है. मार्च 2025 में यह 2.25 प्रतिशत रही थी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि फरवरी में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 2.19 प्रतिशत रही लेकिन गैर-खाद्य प्राथमिक उत्पादों की महंगाई दर 8.80 प्रतिशत रही. इसमें तिलहनों के दाम एक साल पहले की तुलना में 25 प्रतिशत और खनिजों के 11 प्रतिशत बढ़ गये.

सोने-चांदी के दाम लुढ़के, निवेशकों को झटका

3867 रुपए सस्ता हुआ सोना

15508 रुपए नीचे आई चांदी

नई दिल्ली, 16 मार्च. सोना और चांदी के दामों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,963 रुपए गिरकर 1.56 लाख रुपए पर आ गया है. सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,963 रुपए गिरकर 1.56 लाख रुपए पर पहुंच गया है. इससे पहले 13 मार्च को इसकी कीमत करीब 1.58 लाख रुपए थी. वहीं चांदी भी तेज गिरावट के साथ एक किलो 7,695 रुपए सस्ती होकर 2.53 लाख रुपए पर पहुंच गई है. दरअसल, पिछले दो दिनों में सोना 3,867 रुपए और चांदी 15,508 रुपए तक सस्ती हो चुकी है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है.

> इस साल सोने-चांदी के दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जनवरी में जहां सोना रिकॉर्ड 1.76 लाख रुपए तक पहुंच गया था, वहीं अब इसमें करीब 20 हजार रुपए तक की गिरावट आ चुकी है. ऐसे में विशेषज्ञ फिलहाल निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. कमोडिटी बाजार में इस समय तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इससे पहले 13 मार्च को सोना करीब 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. एक किलो चांदी 7,695 रुपए घटकर 2.53 लाख रुपए पर आ गई है. शुक्रवार को इसकी कीमत करीब 2.60 लाख रुपए प्रति किलो थी.

अडानी के हवाई अड्डों पर ड्यूटी-फ्री खरीददारी पर मिलेंगे इंडिगो ब्लूचिप

अहमदाबाद, 16 मार्च. प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो और निजी हवाई अड्डा संचालक अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत इंडिगो ब्लूचिप के सदस्य अब अडानी के हवाई अड्डों पर ड्यूटी-फ्री खरीदारी कर रिवॉर्ड कमा सकेंगे.

साझेदारी के तहत अडानी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले से बुक किये गये ड्यूटी-फ्री उत्पादों पर हर 100 रुपये खर्च करने पर पांच इंडिगो ब्लूचिप्स अर्जित कर सकेंगे. यात्री उड़ान भरने से पहले ही ऑनलाइन उत्पादों को आरक्षित कर उसके लिए भुगतान कर सकते हैं तथा गंतव्य हवाई अड्डे पर अपना बुक कराया हुआ सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं.

इंडिगो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी नीतन चोपड़ा ने कहा, इंडिगो में हम लगातार अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

अडानी ड्यूटी-फ्री के साथ यह साझेदारी उड़ानों से हटकर भी सार्थक रिवॉर्ड प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है. अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के गैर-विमानन कारोबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुचित बंसल ने कहा, हम अडानी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल सर्च, प्री-ऑर्डर की सुविधा और सहज कलेक्शन को एकीकृत कर हवाई अड्डों पर यात्रियों की खरीदारी के अनुभव को बदल रहे हैं.

फरवरी में माल निर्यात बढ़कर 36.61 अरब डॉलर हुआ

नई दिल्ली, 16 मार्च. इस साल जनवरी की तुलना में फरवरी में माल निर्यात में मामूली वृद्धि दर्ज की गयी और यह 36.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया. एक महीने पहले यह आंकड़ा 36.56 अरब डॉलर था.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को आयात-निर्यात के आंकड़े जारी किये. इसमें बताया गया है कि माल आयात जनवरी के 71.24 अरब डॉलर से घटकर फरवरी में 63.71 अरब डॉलर रह गया. इस प्रकार व्यापार घाटा एक महीने पहले के 34.68 अरब डॉलर से कम होकर 27.1 अरब डॉलर पर आ गया. चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में फरवरी 2026 तक देश के माल निर्यात में 1.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक देश का कुल माल निर्यात 402.93 अरब डॉलर रहा. पिछले वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में यह आंकड़ा 395.66 अरब डॉलर था. मंत्रालय ने बताया कि माल और सेवा मिलाकर कुल निर्यात 790.86 अरब डॉलर रहा.

चावल, चीनी, दालों में तेजी, गेहूं नरम, खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 16 मार्च. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल की औसत कीमत बढ़ गयी. चावल के साथ दालों और चीनी में भी तेजी रही. वहीं, गेहूं में गिरावट देखी गयी जबकि खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 69 रुपये बढ़कर 3,850 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं छह रुपये सस्ता हुआ और 2,811 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. आटा भी 22 रुपये उतर गया. दाल-दलहनों में तेजी रही.

दिग्गज कंपनियों में लिवाली से सेंसेक्स उछला

सेंसेक्स 938.93 अंक (1.26 प्रतिशत) की बढ़त पर

निफ्टी-50 सूचकांक भी 257.70 अंक यानी 1.11 प्रतिशत ऊपर

मुंबई, 16 मार्च. घरेलू शेयर बाजारों में दिग्गज और बड़ी कंपनियों में लिवाली से सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 938.93 अंक (1.26 प्रतिशत) की बढ़त में 75,502.85 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 257.70 अंक यानी 1.11 प्रतिशत ऊपर 23,408.80 अंक पर पहुंच गया.

लगातार तीन दिन लुढ़कने के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान में लौटे हैं. आज सुबह गिरावट में खुलने के बाद कुछ ही देर में ये बढ़त में चले गये. दोपहर बाद ग्राफ तेजी से ऊपर गया. बड़ी कंपनियों के विपरीत मझौली तथा छोटी कंपनियों पर दबाव जारी रहा और वृहत बाजार में बिकवाली हावी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.17 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.53 प्रतिशत टूट गया. ऑटो, वित्त, बैंकिंग, एफएमसीजी और धातु समूहों की कंपनियों में जहां लिवाली हुई, वहीं तेल एवं गैस, स्वास्थ्य, फार्मा, रियलटी और रसायन समूहों के सूचकांक नीचे बंद हुए. सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर चार प्रतिशत से अधिक चढ़ा. ट्रेंट में तीन प्रतिशत की तेजी रही.

समाचार विशेष

नीतीश दिल्ली गए तो तेजस्वी को कितना फायदा?

भाजपा से सीधी टक्कर, निशांत भी बनेंगे चुनौती

पटना. अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से हटकर दिल्ली की भूमिका में जाते हैं तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है. लंबे समय से राज्य की राजनीति का केंद्र रहे नीतीश के हटने से सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए नई परिस्थितियां बनेंगी. खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजल्वी यादव के लिए यह स्थिति चुनौती के साथ-साथ अवसर भी लेकर आ सकती है.

अब तक बिहार की राजनीति में भाजपा अक्सर नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में सहयोगी की भूमिका में रही है. अगर सत्ता का केंद्र बदलता है तो तेजस्वी का सीधा मुकाबला भाजपा से होगा. भाजपा अधिक आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है, जिससे विपक्ष की भूमिका निभाना तेजस्वी के लिए आसान नहीं रहेगा.

राजनीतिक बदलाव की स्थिति में जदयू का नेतृत्व नए चेहरे के हाथों में जा सकता है. ऐसे में निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा तेज है. अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी को एक युवा नेता के रूप में नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. हालांकि इससे परिवारवाद के मुद्दे पर जदयू और भाजपा का हमला कुछ कमजोर भी पड़ सकता है.

> **महागठबंधन को साथ रखना बड़ी परीक्षा**
>
> राजनीतिक रूप से विपक्ष को मजबूत करने के लिए महागठबंधन की एकजुटता भी महत्वपूर्ण होगी. चुनाव के बाद सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आए थे. ऐसे में तेजस्वी की रणनीति यह होगी कि वे सभी दलों को साथ लेकर चलें और विपक्ष को एक मजबूत मंच के रूप में स्थापित करें. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति दो बड़े ध्रुवों के बीच सिमट सकती है. ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए यह समय अपनी सक्रियता और राजनीतिक कौशल दिखाने का अवसर है. यदि वे सामाजिक समीकरण और विपक्ष की राजनीति को संतुलित कर पाए, तो राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है.

देश भर में होगा मणिपुर का प्रयोग

इंफाल. मणिपुर विधानसभा ने एक शानदार प्रयोग किया है. राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है. नई सरकार के गठन और कुकी समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं. कुकी और मैतेई का विवाद शांत नहीं हुआ है.

इस विवाद के बीच विधानसभा में वर्चुअल तरीके से सदस्यों के शामिल होने का बंदोबस्त किया गया. विधानसभा के अंदर बड़ी स्क्रीन लगाई गई और विधायकों को अपने घर या कार्यालय से ही कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दी गई.

इस पहले प्रयोग में कुकी जो समुदाय के छह विधायकों ने वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया. उन्होंने अपनी बात कही, जिसे स्क्रीन पर देखा और सुना गया. इसमें राज्य की उप मुख्यमंत्री भी शामिल थीं. दुनिया के अनेक विकसित देशों में यह सुविधा कई साल पहले शुरू हो गई थी. भारत में भी सुप्रीम कोर्ट तक में वर्चुअल सुनवाई और उसके लाइव प्रसारण की सुविधा शुरू हो गई है. अगर देश भर में इस प्रयोग को शुरू किया जाता है तो सांसदों और विधायकों की उपस्थिति बेहतर होगी.

सपा के पीडीए को भेदने बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक

लखनऊ. राजनीतिक पारा चढ़ने के बीच जहां सभी दल चुनावी चौसर बिछाने में जुटे हैं, वहीं मार्च में भाजपा का फोकस संगठन की संरचना पर है. 98 संगठनात्मक जिलों में से चार में अध्यक्ष की घोषणा होनी है, वहीं छह क्षेत्रीय अध्यक्षों पर विरोधी दलों की भी नजर टिकी हुई है.

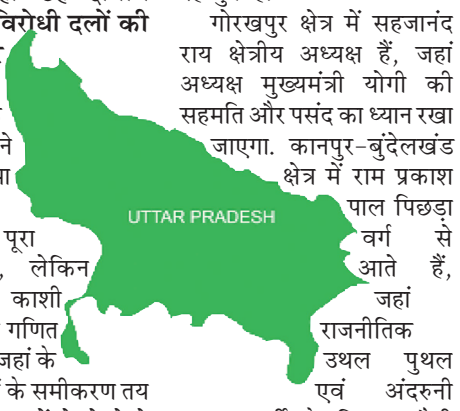

सपा के पीडीए को भेदने के लिए भाजपा जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन पार्टी की सुई काशी क्षेत्र के जातीय गणित पर अटकी है, जहां के बाद अन्य क्षेत्रों के समीकरण तय होंगे. इस बार छह में से दो चेहरे ओबीसी व एक अनुसूचित समाज से अध्यक्ष बनाने की चर्चा है. राजनीतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली क्षेत्र काशी में कुर्मी समाज के दिलीप पटेल अध्यक्ष हैं. इसी समाज से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी आते हैं, ऐसे में दो बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे पटेल की जगह नया जातीय समीकरण अपनाया जा सकता है. वह कुर्मी समाज से आने वाले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह के कार्यकाल में भी क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं.

गोरखपुर क्षेत्र में सहजानंद राय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जहां अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी की सहमति और पसंद का ध्यान रखा जाएगा. कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में राम प्रकाश पाल पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जहां राजनीतिक उथल पुथल एवं अंदरुनी कलह पार्टी के लिए चुनौती बनी. यहां अब जातीय कार्ड बदलने की चर्चा है. अवध, कानुपर एवं गोरखपुर क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, जिसमें से किसी एक जगह दायित्व मिल सकता है.

क्षत्रिय एवं ब्राहमण समाज का भी दावा...

पश्चिम क्षेत्र में जाट के बाद ठाकुर चेहरा आजमाया गया, जहां इस बार गुर्जर, वैश्य, ब्राह्मण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ने भी दावा जताया है. ब्रज क्षेत्र में दुर्गविजय शाक्य क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं. इस क्षेत्र में शाक्य एवं लोध दोनों फैक्टर प्रभावशाली है. पार्टी इस बार लोध समाज के चेहरे को अवसर दे सकती है. हालांकि यहां से क्षत्रिय एवं ब्राहमण समाज के दो चेहरों ने अपना भी दावा जताया है. अवध क्षेत्र में युवा चेहरा कमलेश मिश्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जहां इस बार क्षत्रिय चेहरे को अवसर देने की चर्चा है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि हम सर्वसमाज को लेकर चलते हैं. सभी का सम्मान रखा जाएगा.

विशेष | कांग्रेस ने गठबंधन के लिए हेमंत सोरेन से की मुलाकात

क्या असम में जेएमएम को सीटें देगी कांग्रेस?

रांची. असम विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर-पूर्व की राजनीति में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सक्रियता का असर अब साफ दिखाई देने लगा है.

झारखंड दौरे के बाद असम कांग्रेस नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में गुरुवार को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित राजनीतिक तालमेल और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई.

बैठक में झारखंड में चल रही विकास योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर भी विमर्श किया गया. इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेन्द्र सिंह तथा झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू भी मौजूद रहे. असम के करीब 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं. इनमें ऐसे इलाके भी शामिल हैं जहां झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से दशकों पहले जाकर बसे आदिवासी समुदायों की आबादी प्रभावशाली है. इन्हीं क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठनात्मक विस्तार की कोशिश कर रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया असम दौरे को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. झामुमो इन सीटों पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत कर भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठजोड़ को नई दिशा देना चाहता है.

> **हेमंत सोरेन की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका**
>
> हेमंत सोरेन की सक्रियता को केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं माना जा रहा. हाल के महीनों में उन्होंने कई राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के संकेत दिए हैं. असम की राजनीति में उनकी बढ़ती दिलचस्पी राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी राजनीति को नया स्वर देने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है. यदि असम में विपक्षी दलों के बीच कोई व्यापक तालमेल बनता है तो यह आगामी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. रांची में हुई ताजा मुलाकातों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि असम चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य में नई हलचल शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में यह समीकरण और स्पष्ट हो सकते हैं.

क्षेत्रीय दलों से भी बढ़ रहा संवाद- गुरुवार को इसी कड़ी में असम की क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लूरिनज्योति गोगोई ने भी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच असम के राजनीतिक हालात, चुनावी संभावनाओं और विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई. यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संभावित राजनीतिक तालमेल की दिशा में एक अहम संकेत है.